'अप्प दीपो भव'

# वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2013-15
WPP Licence No.- U(C)-101/2013-15
R.N.I. No. 68180/98

प्रकाशन तिथि– 31 मई, 2013

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन - जस्टिस पब्लिकेशंस, टी–22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001, फोन : 23354841–42

Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com

● वर्ष : 16 ● अंक 13 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● 16 से 31 मई, 2013

बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं।

-गौतम बुद्ध

# डीयू के 4 वर्षीय कार्यक्रम के विरोध में ज्वाइंट एक्शन फ्रंट फार डेमोक्रेटिक एजुकेशन (अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं वामपंथी) का सोनिया गांधी के आवास पर विशाल प्रदर्शन

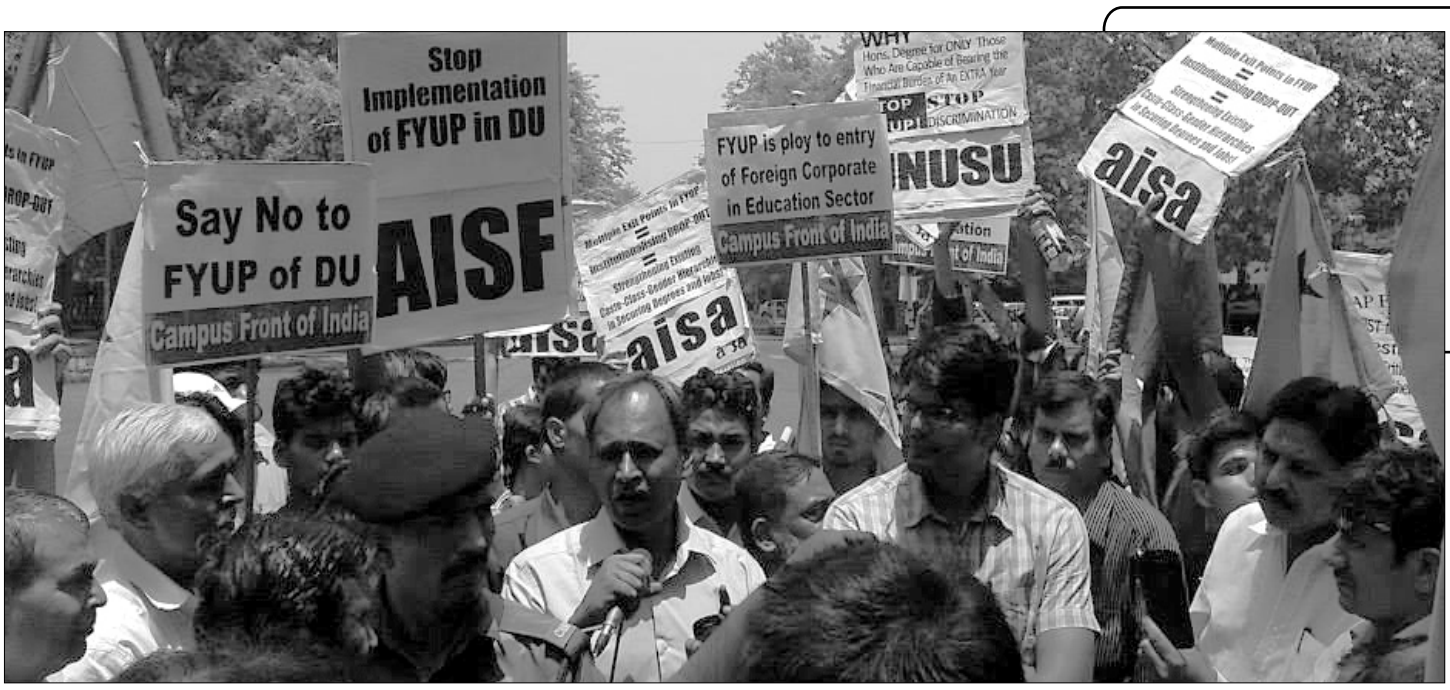


***प्रदर्शन के मौके पर अपार भीड़ को संबोधित करते माननीय डॉ. उदित राज।***

गत् दिनों 19 मई को ज्वाइंट ऐक्शन फ्रंट फार डेमोक्रेटिक एजुकेशन (अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं वामपंथी) की ओर से 10 जनपथ, नई दिल्ली–1 (श्रीमती सोनिया गांधी के आवास) पर प्रोफेसर, शिक्षक, बुद्धिजीवी आदि ने विशाल प्रदर्शन किया। इनका कहना था कि इस प्रदर्शन की आवश्यकता ही न पड़ती यदि प्रधानमंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री व सचिव और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने हमारी बात को सुनी होती। इनके दरवाजे खटखटाए फिर भी दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के शिक्षा विरोधी अभियान अर्थात् चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम को लागू करने की मुहिम को रोका नहीं गया। लगभग 600 विश्वविद्यालय देश में हैं, केवल दिल्ली विश्वविद्यालय ही अकेले अमरीकी शिक्षा व्यवस्था का चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम लागू करने के लिए आमादा क्यों है? इस तरह से सभी विश्वविद्यालय अपनी–अपनी शिक्षा नीति लागू करने लगेगें तो शिक्षा जगत में अनिश्चितता पैदा हो जाएगी। यदि देश की शिक्षा नीति में परिवर्तन करना ही है तो भारत सरकार को शुरुआत करनी चाहिए न कि विश्वविद्यालय के कुलपति को। नीति निर्धारण करने का कार्य कुलपति का नहीं है। यह भ्रम फैलाना कि विश्वविद्यालय की स्वायत्तता का मामला है, निराधार है, बल्कि कुलपति ने सरकार के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप किया है।

यदि 4 वर्ष का स्नातकीय पाठ्यक्रम दिल्ली विश्वविद्यालय में लागू हो जाता है तो छात्रों पर अतिरिक्त वित्तीय भार बढ़ेगा। देहात, गरीब, भारतीय भाषी, आदिवासी, दलित एवं पिछड़े छात्र इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होगें क्योंकि प्रथम वर्ष में 11 फाउंडेशन कोर्स पढ़ने हैं, जिसमें अंग्रेजी, गणित एवं विज्ञान अनिवार्य है। बहुत संभव है कि कुछ छात्र भय से प्रवेश ही न लें और लेगें भी तो बीच में छोड़ देगें। स्नातक की डिग्री में तीन स्तर पैदा हो जाएंगें, जैसे– डिप्लोमा, बैचलर एवं ऑनर्स जो छात्रों में हीनता पैदा करेगी। शिक्षकों को अग्रिम में पाठ्यक्रम को पढ़कर सुझाव देने का मौका नहीं दिया बल्कि मीटिंग के दौरान 11 फाउंडेशन कोर्स, डिसिप्लिन–1 के 18 विषय और डिसिप्लिन–2 के 6 विषय और 4 विषय अप्लाइड के पढ़कर सुझाव देने के लिए बाध्य किया गया जो इतने कम समय में असंभव था। एकेडमिक काउंसिल एवं एक्जक्यूटिव कमेटी में लोभ, लालच एवं भय से पास करा लिया गया है, लेकिन असलियत सामने तब आयी जब 12 मई को बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए जनरल बॉडी मीटिंग में शिक्षकों ने इसके विरूद्ध प्रस्ताव पारित किया। फाउंडेशन कोर्स में 35 अंक लगातार प्रोजेक्ट आदि के द्वारा दिए जाएंगें। डिसिप्लिन–1 में 25 अंक आंतरिक मूल्यांकन के द्वारा, डिसिप्लिन–2 में भी 25 अंक और यही इन वर्गों के छात्रों के साथ भेदभाव करने का अवसर होगा तो जिस तरह से इंजीनियरिंग एवं मेडिकल में फेल किया जाता है और परिणाम यह हो रहा है कि छात्र आत्महत्याएं कर रहे हैं, वही स्थिति यहां होगी। इस विश्वविद्यालय से जब ऑनर्स करके छात्र निकलेगें तो कैसे दूसरे विश्वविद्यालय में प्रवेश पाएंगें और उसी तरह से दूसरे विश्वविद्यालय के छात्रों को परेशानियों का सामना दिल्ली विश्वविद्यालय में करना पड़ेगा।

साधारण परिस्थितियों में यूपीए चेयरपर्सन, श्रीमती सोनिया गांधी, के निवास पर प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं थी। हम मांग करते हैं कि देश के विशिष्ट लोगों की एक समिति बने और जांच करने के बाद ही यदि उचित पाया जाए तो इस स्नातकीय पाठ्यक्रम को लागू किया जाए। सबसे बेहतर तरीका यह है कि पहले देश में बहस चलायी जाए और फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस शिक्षा नीति को लागू करे, यदि आवश्यकता महसूस हो तो। क्यों नहीं सरकार सोच पा रही है कि कुलपति जल्दी में लागू करने के लिए आमादा क्यों हैं? क्या यह कोई छुपा हुआ एजेंडा है? प्रधानमंत्री ने भी यह कहा कि इसे लागू करने में जल्दबाजी क्यों की जा रही है? जनता दल (यू) के अध्यक्ष, श्री शरद यादव, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष, श्री राम विलास पासवान, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, श्री पी.एल. पुनिया, सीपीआई नेता श्री डी. राजा एवं सीताराम येचुरी ने हस्ताक्षर करके हमारी मांगों का समर्थन किया है। इस प्रदर्शन के माध्यम से मांग किया गया है कि चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम को लागू करने से फौरन रोका जाए और विश्वविद्यालय के कुलपति को बर्खास्त किया जाए।

***10, जनपथ (सोनिया गांधी के आवास) पर प्रदर्शन करते लोग***

# बौद्ध उन्नायक जगदीश काश्यप

**प्रेम कुमार मणि**

बिहार के आधुनिक इतिहास में बौद्ध दर्शन के पुनरुद्धार का श्रेय जिस एक व्यक्ति को जाना चाहिए वे हैं भिक्षु जगदीश काश्यप। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस महान साधक के नाम से ज्यादातर लोग अपरिचित हैं। नव नालंदा महाविहार, जिसे सामान्य तौर से पालि इंस्टीट्यूट के रूप में जाना जाता है, भिक्षु जगदीश काश्यप के प्रयत्नों का ही प्रतिफल है। आज एक बार फिर नालंदा में विश्व स्तर के विश्वविद्यालय की स्थापना की कोशिश हो रही है। यदि यह हुआ तो इसे काश्यप जी के सपनों का साकार होना ही कहेंगे।

भिक्षु जगदीश काश्यप का जन्म रांची में 2 मई, 1908 को एक मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ था। इनका कुल नाम जगदीश नारायण था। जब वे राहुल सांकृत्यायन से मिले तो उनकी मेधा से बहुत प्रभावित हुए। काश्यप जी राहुल जी के द्वारा बुद्ध से कुछ–कुछ परिचित हो चुके थे। साम्राज्यवाद–विरोधी संग्राम में वे कांग्रेस के मंच से सक्रिय भी हो चुके थे। मन में विद्रोही भावनाएं थी। इन सबकी संगति और राहुल सांकृत्यायन का सान्निध्य। काश्यपजी बौद्ध धर्म दर्शन और खासकर पालि भाषा के अध्ययन के लिए उत्सुक हुए। उस समय पालि त्रिपिटक के अध्ययन का सबसे बड़ा केंद्र श्रीलंका का विद्यालंकारा महाविहार था। काश्यप जी ने विद्यालंकारधिपति को पत्र लिखा और वहां आने की अनुमति मांगी। लेकिन वहां जाने का मार्ग प्रशस्त किया राहुल जी ने। पटना में उन दिनों काशी प्रसाद जायसवाल विद्वानों के आकर्षण का केंद्र हुआ करते थे। राहुल जी से काश्यप जी की मुलाकात इन्हीं के घर हुई। राहुल जी ने काश्यप जी को पत्र देकर श्रीलंका विदा किया।

श्रीलंका में जगदीश नारायण ने धम्म की प्रव्रज्या ग्रहण कर ली और जगदीश काश्यप हो गए। कहते हैं जगदीश काश्यप नारायण ने मां और अन्य पारिवारिक सदस्यों से इस प्रव्रज्या के लिए इजाजत ली थी। काश्यपजी ने कठिन परिश्रम से जल्दी ही त्रिपिटाकाचार्य में उत्तीर्णता प्राप्त कर ली। पालि भाषा पर अधिकार प्राप्त कर इन्होंने श्रीलंका में बौद्धधर्म की स्थिति का अध्ययन किया और संस्कृत में इस विषय पर एक किताब लिखी। वहां के विद्वानों के बीच इनकी प्रतिष्ठा थी। राहुल जी भी इन पर नजर रखे हुए थे। 1934 में काश्यप जी जब भारत लौटे तो राहुल जी इन्हें साथ लेकर जापान चले गए। पूरब के अनेक बौद्ध देशों में घूमकर दोनों विद्वानों ने अपना ज्ञान बढ़ाया। इस यात्रा में काश्यप जी ने चीनी भाषा सीख ली और दीघनिकाय का अनुवाद कार्य पूरा लिया। इसके साथ–साथ बौद्धों के ध्यानयोग जिसे विपस्यना कहते हैं, में काश्यप जी ने निपुणता प्राप्त कर ली। उन पर ज्यादा से ज्यादा काम करने का धुन सवार था। जल्दी ही उन्होंने प्रमुख बौद्धग्रंथ मिलिन्दपन्हों का भी हिंदी में अनुवाद कर दिया।

भारत लौटने पर काश्यप जी ने सारनाथ को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। उस समय वहां अनेक बौद्ध विद्वान रहते थे। यहीं पर इन्होंने प्रकांड विद्वान धम्मानंद कोसाम्बी से अभिधम्म और विसुद्धिमग्ग जैसे ग्रंथों का अध्ययन किया। उनकी विद्धता की चारो ओर प्रतिष्ठा हो रही थी, किंतु काश्यप जी को थोथे विद्वान बना रहना स्वीकार नहीं था। बौद्ध धर्म को लेकर एक सांस्कृतिक आंदोलन की बात उनके मन में थी और वे एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहते थे। उनके मन में यह भी था कि उनके अपने बिहार प्रांत में ही बौद्ध धर्म की कोई चर्चा नहीं है। बोधगया का मंदिर भी तब जर्जर हाल में था। जनता में बुद्ध का कोई नाम लेने वाला नहीं था। यह सब सोचकर काश्यप जी ने वाराणसी से अपना आसन उठाया और मगध क्षेत्र में आकर जम गए। वे गांव–गांव घूमते। मगही भाषा में लोगों को बुद्ध व उनके विचारों के बारे में बतलाते और कोई ना कोई केंद्र अथवा कुटी बनाने का जुगाड़ तलाशते। इसी बीच वे नालंदा में जमे। वहां नालंदा कॉलेज में पालि के अध्ययन की व्यवस्था की। कोई शिक्षक ना मिला तो वे स्वंय शिक्षक बन गए। इसी बीच तत्कालीन शिक्षा सचिव जगदीशचंद्र माथुर से मिलकर उन्हें नालंदा में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पालि अध्ययन संस्थान खोलने के लिए राजी कर लिया। इसके बाद वे स्वयं नालंदा में आकर संभावनाओं की तलाश करने लगे। सैकड़ों लोगों से इन्होंने मुलाकात की। वह भी ऐसे कार्य के लिए जिसे जनता जानती तक नहीं थी कि पालि और त्रिपिटक क्या बला है। इसी क्रम में वे इस्लामपुर के मुस्लिम जमींदार से मिले और कहा कि आपके पूर्वजों ने कभी नालंदा को जलाया था, मैं आपसे उसे फिर से बसाने के लिए दान मांगने आया हूं। मुस्लिम जमींदार काश्यप जी से बहुत प्रभावित हुए और तुरंत ग्यारह एकड़ जमीन पालि संस्थान के लिए काश्यप जी को दे दिया। इसी जमीन पर 20 नवंबर, 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने नव नालंदा विहार की आधारशिला रखी। नव नालंदा महाविहार काश्यप जी की देन है। इसे खड़ा कर उन्होंने एक बार फिर बिहार में बौद्ध धर्म के अध्ययन–अध्यापन की शुरुआत कर दी। आज यह संस्थान उनकी कीर्ति के रूप में खड़ा है और बार–बार हमें उस प्राचीन विश्वविश्रुत विश्वविद्यालय की याद दिलाता है।

उस महाविहार की स्थापना के बाद काश्यप जी का ध्यान लुप्त पालि वांड्मय की ओर गया। संपूर्ण पालि वांड्मय कई विदेशी लिपियों में तो था, लेकिन नागरी लिपि में ही नहीं था। पालि टेक्स्ट सोसाइटी लंदन ने सिंहली से रोमन लिपि में पालि वांड्मय का अनुवाद कराया था। इस अनुवाद से नागरी में अनुवाद कराना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। जगदीश काश्यप ने इसे पूरा किया। संपूर्ण पालि वांड्मय आज इकतालीस खंडों में नागरी लिपि में उपलब्ध है। राज्य और केंद्र सरकार से निवेदन कर इसके प्रकाशन की भी व्यवस्था काश्यप जी ने की। यह एक ऐसा कार्य है जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा।

काश्यप जी का नाम राहुल सांकृत्यायन और भदंत आनंद कौशल्यायन के साथ आधुनिक भारत में बौद्ध धर्म के उन्नायकों में लिया जाता है। तीनों मिलकर एक त्रयी बनाते हैं। इन तीनों ने मिलकर महान बौद्ध भिक्षु धम्मपाल अनागरिका के मिशन को पूरा किया। आज फिर देश और बिहार प्रदेश में बौद्ध धर्म की चर्चा में है। इस चर्चा के बीच भिक्षु जगदीश काश्यप जी का स्मरण तालाब के जलतरंगों के बीच शुभ्रकमल की तरह खिलता प्रतीत होता है। आने वाले समय में जब बिहार और प्रबुद्ध होगा तब काश्यप जी के महत्व को हम और गंभीरता से समझ सकेंगे।

काश्यप जी का निधन 28 जनवरी, 1976 को राजगृह में हुआ। नालंदा में उनकी अंत्येष्टि हुइ। नव नालंदा महाविहार के प्रांगण में उनकी स्फटिक प्रतिमा लगी है। कभी मगध के ही एक भिक्षु शीलभद्र ने नालंदा की कीर्ति में चार चांद लगाया था। मगध के इस आधुनिक भिक्षु ने भिक्षु महाकाश्यप और शीलभद्र की परंपरा को इस जमाने तक खींच लाया।

**(साभार– फॉरवर्ड प्रेस)**

## दलित अधिकार केंद व राष्ट्रीय दलित न्याय आंदोलन के संयुक्त तत्वाधान में सम्मेलन का समापन

**चन्दा लाल बैरवा**

दलित अधिकार केंद्र जयपुर व राष्ट्रीय दलित न्याय आंदोलन, नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में गत् दिनों 27 अप्रैल, 2013 को सम्मेलन का उद्घाटन सिक्किम उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री सुरेंद्रनाथ भार्गव ने किया। इन्होंने कहा कि मानवाधिकार प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को जन्म के साथ ही उसको मिल जाते हैं लेकिन कुछ समुदाय ऐसा है जिनको जाति, धर्म, लिंग के आधारा पर मूलभूत सुविधाओं से वंचित करना उनके मानवाधिकारों का सबसे बड़ा हनन है। दलित, महिलाएं, मजदूर किसान एक ऐसा समुदाय है जिनका सबसे ज्यादा मानवाधिकारों का हनन होता है क्योंकि यह वर्ग आर्थिक रूप से सबसे नीचे के पायदान पर है। अधिवक्ता समाज का प्रतिष्ठित वर्ग है इसलिए अधिवक्ताओं को इनको न्याय दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

मुख्य अधिवक्ता के रूप में दलित अधिकार केंद्र के संरक्षक पी. एल. मीमरौठ ने राजस्थान के दलितों की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 बने हुए 23 वर्ष हो गये लेकिन पुलिस प्रशासन की दलितों के प्रति उदासीनता, राजनैतिक हस्तक्षेप, बढ़ता भ्रष्टाचार आदि के कारण से उक्त कानून का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है जिसके कारण से दलितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। यह स्थिति कमोबेश राजस्थान की ही नहीं अपितु पूरे देश की यही स्थिति है। पिछले तीन वर्षों में 241 दलितों की हत्या की गई जिनमें 50 प्रतिशत मामलों में एफआर लगा दी, 30 प्रतिशत प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, अन्य केसों में राजनीतिक दबाव के कारण राजीनामा व समझौता हो गया। मात्र तीन प्रकरणों में सजा हुई जिससे साफ जाहिर होता है कि न्याय का प्रतिशत बहुत कम है।

## एक बहादुर रेजीमेंट की गाथा

**अशोक चौधरी**

चमार रेजीमेंट और अनुसूचित जातियों की सेना में भागीदारी, हवलदार सुलतान सिंह की पहली पुस्तक है। लेखक ने इस कृति के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है कि एक ऐसी रेजीमेंट जो कि आज अस्तित्व में नहीं है, उसके जवान कितने बहादुर थे।

पुस्तक के आवरण पर छपा वाक्य जब आप घर जाएं तो उनसे जरूर कहना कि उनके कल के लिए हमने अपना आज दिया है। ये शब्द कोहिमा शहीद स्मारक पर आज भी अंकित है। पुस्तक उन बहादुर जवानों की याद में लिखी गई है, जिन्होंने दुश्मनों से लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। लेखक ने ऐतिहासिक संदर्भों के माध्यम से द्वितीय विश्व युद्ध में चमार रेजीमेंट के जवानों की शौर्य गाथा को वर्णित किया है। पुस्तक बताती है कि रेजीमेंट के उसी समुदाय के जवानों ने रणक्षेत्र में कितनी बहादुरी का परिचय दिया था, जिस समुदाय के सदस्यों को आज गुणविहीन और डरपोक घोषित कर उच्च पदों पर आसीन नहीं किया जा रहा है। लेखक पलासी के युद्ध का संदर्भ देते हुए लिखते हैं कि जंग में अंग्रेज सेना के पास तीन हजार युवक थे जो

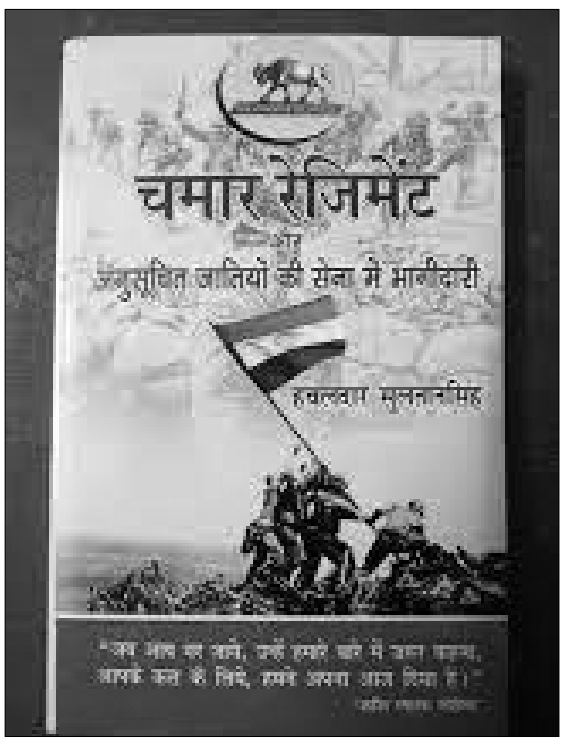


अनुसूचित जाति के थे और मीर जाफर के पास 50,000 सैनिक थे। इसके बाद भी अंग्रेज सेना के जवानों ने 50,000 सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए थे। जो उनकी वीरता का परिचायक था। पुस्तक लेखक की कठिन मेहनत और लंबे शोध का परिणाम है। यह पुस्तक कोई कहानी नहीं है बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसे नकारना शायद ही किसी के बस की बात हो। पुस्तक वर्तमान सेना में जो मिथक व्याप्त हैं उन्हें दूर करने की जरूरत पर बहस की शुरुआत करेगी। पुस्तक में केवल चमार रेजीमेंट पर ही नहीं बल्कि सेना से जुड़े हर उस पहलू पर रोशनी डालने का प्रयास किया गया है जिसके बारे में आम लोगों में जिज्ञासा है।

मसलन, सैनिक लड़ता क्यों है, सैनिक सेवाओं में प्राप्त होने वाली सुविधाएं और प्रत्येक नागरिक का सैन्य सेवा करने का अधिकार। भीमराव अंबेडकर के सेना के बारे में विचारों का भी पुस्तक में समावेश है। कुल मिलाकर यह पुस्तक मात्र नहीं है। यह ब्रिटिश काल से लेकर अब तक के सेना के इतिहास का एक सच्चा दस्तावेज है। यह सेना पर एक शोध प्रबंध है।

**(साभार– फॉरवर्ड प्रेस)**

# डीयू में चार वर्षीय स्नातक का सच

**डॉ. उदित राज**

देश में दिल्ली विश्वविद्यालय ही अनोखा होगा, जो 4 वर्ष का बी.ए. ऑनर्स का कार्यक्रम लागू करने के लिए आमादा है। इसके कुलपति को लगता है कि इससे छात्रों का बड़ा भला होगा। बहुत संभव है कि कुलपति या मंत्री कभी अमेरिका गए हों और इसके बारे में सुनकर बड़ा प्रभावित हुए हों या अन्य स्रोतों से जानकारी प्राप्त हुई हो कि चार वर्ष के स्नातक के कार्यक्रम से छात्रों की वैतरणी पार हो जाएगी। ऐसी ही नकल की वजह से कुछ समय पहले इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की पढ़ाई की धूम मची थी और नतीजा यह हुआ कि आज लाखों लड़के इंजीनियरिंग व प्रबंधन की डिग्री लेकर घूम रहे हैं। यह अमरीकी कार्यक्रम है और यह जरूरी नहीं है कि जो सारी बातें यूरोप एवं अमेरिका में की जा रही हैं, वे सभी यहां भी लाभकारी हों। प्रथम दृष्ट्या इस कोर्स को देखने से बात स्पष्ट होती है कि चार वर्ष तक ज्यादातर अभिजात्य वर्ग के ही विद्यार्थी अध्ययन कर सकेगें। लगभग दो दशक से अघोषित रूप से ऐसी नीति चल रही है कि शिक्षा दो प्रकार की हो –एक महंगी व नई पठन–सामग्री के साथ और दूसरी पूर्व जैसी। शिक्षा का निजीकरण एवं व्यवसायीकरण इतना ज्यादा तेजी से हुआ कि अब माना जा रहा है कि इससे ज्यादा सुरक्षित आमदनी का कोई और उद्योग नहीं रह गया है।

देश में 600 विश्वविद्यालय हैं, वे क्या दिल्ली विश्वविद्यालय से कमतर हैं? दिल्ली विश्वविद्यालय की मुहिम से तो यही लगता है कि यदि इस कार्यक्रम को लागू करना ही था तो देश में पहले बहस होनी चाहिए थी और उसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं यूजीसी को विचार करना चाहिए था कि क्या यह कार्यक्रम शिक्षा के प्रचार–प्रसार में सहयोगी होगा या नहीं। वास्तव में इससे लोग क्या ज्यादा रोजगार ले सकेगें? ऐसा करने के बजाय दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति ने अपने स्तर पर यह करने की ठानी। उनकी दलील है कि इससे लोगों को रोजगार मिलेगा अर्थात् छात्रों का भला चाहते हैं। वे इतना ही छात्रों के शुभचिंतक हैं तो पहले की समस्याओं को निबटाने के बाद इसे करते तो बात समझ में आती। देश में यही विश्वविद्यालय ऐसा है, जिसने 2006 की शिक्षा नीति के अनुसार ऐसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर के पद पर आरक्षण नहीं दिया। हजारों वर्षों से जो समाज पिछड़ा था पहले उसको अधिकार देने के लिए कदम उठाते तो लगता कि वे छात्र एवं समाज के शुभचिंतक हैं। विश्वविद्यालय के तमाम प्रोफेसरों ने कहा कि कुलपति शिक्षा जगत् में सुधारक की शोहरत प्राप्त करने के साथ–साथ अमरीका की शिक्षा लाबी को खुश कर तमाम व्यक्तिगत् लाभ लेना चाह रहे हैं। इस बात में दम भी है, इसलिए कि सबको बेहतरीन शिक्षा देने की नीयत होती तो विश्वविद्यालय में बुनियादी सुविधाओं की पहले कमी को पूरा करते, छात्र एवं अध्यापक के अनुपात को संतुलित करने सहित तमाम और समस्याएं जैसे – छात्रावास, वजीफा आदि पर ध्यान दिया जाता।

देश के महत्वपूर्ण लोग जैसे डॉ0 उदित राज, डॉ0 हैनी बाबू, डॉ0 शास्वती मजूमदार, डॉ0 एस. के. सागर, डॉ0 विजया वेंकटरमन, डॉ0 सुकुमार, डॉ0 केदार मंडल, डॉ0 कौशल पवार, डॉ0 सतवीर बरवाल, डॉ0 श्री भगवान ठाकुर, डॉ0 प्रभाकर पलाका, अनूप पटेल, लेनिन विनोबर, डॉ0 देव कुमार आदि ने ज्वाइंट एक्शन फ्रंट फार डेमोक्रेटिक एजुकेशन (अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं वामपंथी) का गठन इसलिए किया कि दिल्ली विश्वविद्यालय में चार वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम जितना लाभ का नहीं होगा उससे कहीं ज्यादा हानिकारक सिद्ध होगा। मानव संसाधन विकास मंत्री, श्री पल्लमराजू से मिलकर अपना पक्ष रखा और उसके बाद शिक्षा सचिव से, लेकिन उनको पहले से ही कुलपति ने अपने आत्मविश्वास में ले लिया है। ये दोनो प्रतिनिधिमंडल के लोगों के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए तो यह कहते हुए अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होने की कोशिश किए कि विश्वविद्यालय के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगें। मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, श्री शशि थरूर ने तो सीमा ही पार कर दिया है कि वे आंतरिक मामले में दखल नहीं देगें। यदि ऐसा है तो फिर वे क्यों विभाग के मंत्री हैं? क्या विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के संबंध में कोई और मंत्री होना चाहिए, अगर ये हस्तक्षेप नहीं कर सकते? असाधारण परिस्थिति में मंत्री हस्तक्षेप नहीं करेगा तो लोग अपनी फरियाद लेकर कहां जाएंगें? तमाम विद्यार्थियों एवं शिक्षकों का आरोप है कि कुलपति ने शिक्षकों को अग्रिम में एजेंडा नहीं दिया। मीटिंग के दौरान उन्हें 11 फाउंडेशन कोर्स, 18 डिसिप्लिन–1 के विषय, 6 डिसिप्लिन–2 के विषय और 4 अप्लाइड के विषय को पढ़कर एवं समझकर वहीं पर टिप्पणी, सुझाव एवं स्वीकृति देना था। 500 से अधिक पृष्ठ की पठन सामाग्री को इतने कम समय में मीटिंग के दौरान पढ़कर कैसे स्वीकृति दी जा सकती है। उनसे जबरन स्वीकृति ली गयी (शिक्षक : प्रो0 विजया वेंकटरमन का कथन)। एकेडमिक काउंसिल एवं एक्जीक्यूटिव कमेटी को भी लोभ–लालच एवं भय से प्रभावित किया गया। कुलपति द्वारा यह कहा जाना कि उन्हें इन कमेटियों का समर्थन हासिल है, तो यह भी इस समय बता देना उचित होगा कि कभी–कभी छल–कपट से माहौल को अपने पक्ष में कर लिया जाता है और लोग बाद में समझ पाते हैं। 12 मई को शिक्षकों की जनरल बॉडी मीटिंग में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ कि इस पाठ्यक्रम को जल्दी में न लागू किया जाए।

इस चार वर्ष के पाठ्यक्रम में 11 फाउंडेशन कोर्स पढ़ाया जाएगा और अंग्रेजी व गणित अनिवार्य होगा। देहात, हिन्दी भाषी, दलित, आदिवासी, गरीब एवं पिछड़े छात्र किसी तरह हाईस्कूल में गणित और अंग्रेजी मेहनत–मशक्कत एवं रटकर पास हो जाते हैं और यही दुआ करते हैं कि आगे ये विषय पढ़ने को न मिलें, लेकिन अब उन्हें फिर से पढ़ना पड़ेगा तो बहुत संभव है कि काफी छात्र प्रथम वर्ष में ही छोड़ दें या प्रवेश लेने की हिम्मत ही न करें। इस कार्यक्रम में दो एक्जिट प्वाइंट हैं, एक–दो वर्ष के बाद छात्र डिप्लोमा की डिग्री लेकर पढ़ाई छोड़ सकते हैं और जो किसी तरह से दो वर्ष तक खींच लिया तो तीसरे वर्ष में जाकर बैचलर की डिग्री लेकर भाग खड़े हो सकते हैं। संभव है कम छात्र ही होगें जो चार वर्ष तक अध्ययन करके आनर्स की डिग्री प्राप्त करेगें। इस तरह से डिप्लोमा वालों को चपरासी, बैचलर उससे कुछ ऊपर की नौकरी और आनर्स वाले हुक्मरान बनाने के लिए तैयार किए जाएंगें। नॉर्थ ईस्ट के छात्रों को हिंदी पढ़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए अर्थात् उन्हें छूट देना चाहिए। साथ ही उत्तीर्ण करने का प्राप्तांक 40 प्रतिशत न करके 33 प्रतिशत किया जाना चाहिए। फाउंडेशन कोर्स में 35 अंक लगातार प्रोजेक्ट आदि से दिए जाएंगें, डिसिप्लिन–1 में 25 अंक आंतरिक मूल्यांकन के द्वारा, डिसिप्लिन–2 में भी 25 अंक इसी तरह से दिए जाएंगें और अप्लाइड कोर्स में भी शिक्षकों को लगातार मूल्यांकन के द्वारा अंक देने के अधिकार होगें। विशेष रूप से मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में आंतरिक मूल्यांकन की वजह से छात्रों का न केवल व्यक्तित्व उभरने से रोका जाता है, बल्कि कम अंक के साथ–साथ तमाम तरह के भेदभाव किए जाते हैं। इसलिए यहां आत्महत्या की वारदातें अधिक होती हैं और चार वर्ष के पाठ्यक्रम में भी यही होने वाला है। छात्रों पर अतिरिक्त वित्तीय भार बढ़ेगा। यह सभी जानते हैं कि ज्यादातर छात्र दूर–दराज से आकर निजी व्यवस्था पर रहते हैं। चार साल की अवधि भी ज्यादा है। जो चार साल में ऑनर्स की डिग्री प्राप्त करेगा तो अन्य 6 सौ विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर में कैसे प्रवेश लेगा? पूरे देश में दो या तीन वर्ष में बी.ए. की डिग्री मिल रही है तो जो छात्र शेष विश्वविद्यालयों से बी.ए. करेगें तो वे कैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में एम.ए. में प्रवेश लेगें? इस तरह के तमाम सारे अंतर्विरोध हैं, जिसका कोई जवाब नहीं है। 11 फाउंडेशन कोर्स के अतिरिक्त 18 विषय छात्रों को पढ़ना पड़ेगा। कुछ घंटों में ही इन पाठ्यक्रमों को संस्तुति देने के लिए शिक्षकों पर दबाव बनाया गया। कुछ ने विरोध भी किया लेकिन दबाव, छल–कपट एवं लोभ से पास करा लिया गया। आखिर रातोरात इस कार्यक्रम को लागू करने की क्या जल्दी थी? इसके पीछे किसका स्वार्थ है? इसको जानना मुश्किल नहीं है।

एक तरफ सरकार देश को शिक्षित करने का वायदा कर रही है तो दूसरी तरफ ऐसी भी नीति का समर्थन कर रही है, जिससे शिक्षा अमीरों तक ही सीमित रहे। अंततः इससे शिक्षा के निजीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। यह अमरीका की शिक्षा लाबी के लिए प्रवेश का द्वार सिद्ध होगा। आखिर यूजीसी क्यों इतनी मेहरबान है? नेशनल एसेसमेंट एक्रीडिशन काउंसिल के द्वारा अभी तक 600 में से 200 विश्वविद्यालयों, 36,000 में 6000 कॉलेजों को ही सर्टिफाई किया गया है और बहुत संभव है कि अमरीकी शिक्षा लाबी परोक्ष रूप से दबाव बनाए कि काउंसिल के पास पर्याप्त ताना–बाना नहीं है कि वह शेष को सर्टिफाई करे। अतः बाहरी एजेंसियों को प्रवेश करने का अवसर मिलेगा जो भारी पैसा लेकर सर्टिफाई करेगीं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने सर्टिफाई करने से मना कर दिया है तो ऐसे में कैसे यूजीसी चेयरमैन ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति को इंचार्ज बनाया। इससे यू.जी.सी. के चेयरमैन एवं कुलपति में सांठ–गांठ की बू आती है। जिस रफ्तार से शिक्षा का निजीकरण हुआ है, वह महंगी हुई और उत्कृष्ट शिक्षा आम लोगों की पहुंच से बाहर हो चुकी है। परोक्ष रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय की मुहिम भी इसी नीति को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है।

## पाठकों से अपील

**'वॉयस ऑफ बुद्धा' के सभी पाठकों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक वार्षिक शुल्क/शुल्क जमा नहीं किया है, वे शीघ्र ही बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के नाम से टी–22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 को भेजें। शुल्क 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के खाता संख्या 0636000102165381 जो पंजाब नेशनल बैंक की जनपथ ब्रांच में है, सीधे जमा किया जा सकता है। जमा कराने के तुरंत बाद इसकी सूचना ईमेल, दूरभाष या पत्र द्वारा दें। कृपया 'वॉयस ऑफ बुद्धा' के नाम ड्राफ्ट या पैसा न भेजें और मनीआर्डर द्वारा भी शुल्क न भेजें। जिन लोगों के पास 'वॉयस ऑफ बुद्धा' नहीं पहुंच रहा है, वे सदस्यता संख्या सहित लिखें और संबंधित डाकघर से भी सम्पर्क करें। आर्थिक स्थिति दयनीय है, अतः इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए खुलकर दान या चंदा दें।**

**सहयोग राशिः**

**पांच वर्ष : 600 रुपए**

**एक वर्ष : 150 रुपए**

# भारतीय मीडिया का सबसे बड़ा गैंग

## भारतीय मीडिया की हकीकत

अरुंधती रॉय, प्रणव रॉय (नेहरु डायनेस्टी टीवी– एनडीटीवी) की भांजी हैं। प्रणव रॉय "काउंसिल ऑन फ़ॉरेन रिलेशन्स" के इंटरनेशनल सलाहकार बोर्ड के सदस्य हैं। इसी बोर्ड के एक अन्य सदस्य हैं मुकेश अम्बानी। प्रणव रॉय की पत्नी हैं राधिका रॉय। राधिका रॉय, बृंदा करात की बहन हैं। बृंदा करात, प्रकाश करात (सीपीआई) की पत्नी हैं। प्रकाश करात चेन्नै के "डिबेटिंग क्लब" के सदस्य थे। एन राम, पी चिदम्बरम और मैथिली शिवरामन भी इस ग्रुप के सदस्य थे। इस ग्रुप ने एक पत्रिका शुरु की थी "रैडिकल रीव्यू"। सीपीआई(एम) के एक वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी की पत्नी हैं सीमा चिश्ती। सीमा चिश्ती इंडियन एक्सप्रेस की "रेजिडेण्ट एडीटर" हैं। बरखा दत्त एनडीटीवी में काम करती हैं। बरखा दत्त की माँ हैं श्रीमती प्रभा दत्त। प्रभा दत्त हिन्दुस्तान टाइम्स की मुख्य रिपोर्टर थीं। राजदीप सरदेसाई पहले एनडीटीवी में थे, अब सीएनएन–आईबीएन में हैं। राजदीप सरदेसाई की पत्नी हैं सागरिका घोष। सागरिका घोष के पिता हैं दूरदर्शन के पूर्व महानिदेशक भास्कर घोष। सागरिका घोष की आंटी रूमा पॉल हैं। रूमा पॉल उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश हैं। सागरिका घोष की दूसरी आंटी अरुंधती घोष हैं। अरुंधती घोष संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थाई प्रतिनिधि हैं। सीएनएन–आईबीएन का "ग्लोबल बिजनेस नेटवर्क" (जीबीएन) से व्यावसायिक समझौता है। जीबीएन टर्नर इंटरनेशनल और नेटवर्क–18 की एक कम्पनी है। एनडीटीवी भारत का एकमात्र चैनल है को "अधिकृत रूप से" पाकिस्तान में दिखाया जाता है। दिलीप डिसूज़ा पीआईपीएफडी (पाकिस्तान–इंडिया पीपल्स् फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी) के सदस्य हैं। दिलीप डिसूज़ा के पिता हैं जोसेफ़ बेन डिसूज़ा। जोसेफ़ बेन डिसूज़ा महाराष्ट्र सरकार के पूर्व सचिव रह चुके हैं। तीस्ता सीतलवाड़ भी पीआईपीएफडी की सदस्य हैं। तीस्ता सीतलवाड़ के पति हैं जावेद आनन्द। जावेद आनन्द एक कम्पनी सबरंग कम्युनिकेशन और एक संस्था "मुस्लिम फ़ॉर सेकुलर डेमोक्रेसी" चलाते हैं। इस संस्था के प्रवक्ता हैं जावेद अख्तर। जावेद अख्तर की पत्नी हैं शबाना आज़मी। करण थापर आईटीवी के मालिक हैं। आईटीवी बीबीसी के लिये कार्यक्रमों का भी निर्माण करती है। करण थापर के पिता थे जनरल प्राणनाथ थापर (1962 का चीन युद्ध इन्हीं के नेतृत्व में हारा गया था)। करण थापर बेनज़ीर भुट्टो और ज़रदारी के बहुत अच्छे मित्रों में शुमार हैं। करण थापर के मामा की शादी नयनतारा सहगल से हुई है। नयनतारा सहगल, विजयलक्ष्मी पंडित की बेटी हैं। विजयलक्ष्मी पंडित, जवाहरलाल नेहरू की बहन हैं। मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आन्दोलन की मुख्य प्रवक्ता और कार्यकर्ता हैं। नबाआं को मदद मिलती है पैट्रिक मेकुल्ली से जो कि "इंटरनेशनल रिवर्स नेटवर्क (आईआरएन)" संगठन में हैं। अंगना चटर्जी आईआरएन की बोर्ड सदस्या हैं। अंगना चटर्जी पीआरओएक्सएसए (प्रोगेसिव साउथ एशियन एक्सचेंज नेटवर्क) की भी सदस्या हैं। पीआरओएक्सएसए संस्था, एफओआईएल (फ्रेंड्स ऑफ इंडियन लेफ्टिस्ट) से पैसा पाती है। अंगना चटर्जी के पति हैं रिचर्ड शेपायरो। एफओआईएल के सह–संस्थापक हैं अमेरिकी वामपंथी बिजू मैथ्यू। राहुल बोस (अभिनेता) खालिद अंसारी के रिश्ते में हैं। खालिद अंसारी "मिड–डे" पब्लिकेशन के अध्यक्ष हैं। खालिद अंसारी एमसी मीडिया लिमिटेड के भी अध्यक्ष हैं। खालिद अंसारी, अब्दुल हमीद अंसारी के पिता हैं। अब्दुल हमीद अंसारी कांग्रेसी हैं। एवेंजेलिस्ट ईसाई और हिन्दुओं के खास आलोचक जॉन दयाल मिड–डे के दिल्ली संस्करण के प्रभारी हैं। नरसिम्हन राम (यानी एन राम) दक्षिण के प्रसिद्ध अखबार "द हिन्दू" के मुख्य सम्पादक हैं। एन राम की पहली पत्नी का नाम है सूसन। सूसन एक आयरिश हैं जो भारत में ऑक्सफ़ोर्ड पब्लिकेशन की इंचार्ज हैं। विद्या राम, एन राम की पुत्री हैं, वे भी एक पत्रकार हैं। एन राम की हालिया पत्नी मरियम हैं। त्रिचूर में आयोजित कैथोलिक बिशपों की एक मीटिंग में एन राम, जेनिफ़र अरुल और के एम रॉय ने भाग लिया है। जेनिफ़र अरुल, एनडीटीवी की दक्षिण भारत की प्रभारी हैं। जबकि के एम रॉय "द हिन्दू" के संवाददाता हैं। के एम रॉय "मंगलम" पब्लिकेशन के सम्पादक मंडल सदस्य भी हैं। मंगलम ग्रुप पब्लिकेशन एमसी वर्गीज़ ने शुरु किया है। के एम रॉय को "ऑल इंडिया कैथोलिक यूनियन लाइफ़टाइम अवार्ड" से सम्मानित किया गया है। "ऑल इंडिया कैथोलिक यूनियन" के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं जॉन दयाल। जॉन दयाल "ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल"(एआईसीसी) के सचिव भी हैं। एआईसीसी के अध्यक्ष हैं डॉ जोसेफ़ डिसूज़ा। जोसेफ़ डिसूज़ा ने "दलित फ्रीडम नेटवर्क" की स्थापना की है। दलित फ्रीडम नेटवर्क की सहयोगी संस्था है "ऑपरेशन मोबिलाइज़ेशन इंडिया" (ओएम इंडिया)। ओएम इंडिया के दक्षिण भारत प्रभारी हैं कुमार स्वामी। कुमार स्वामी कर्नाटक राज्य के मानवाधिकार आयोग के सदस्य भी हैं। ओएम इंडिया के उत्तर भारत प्रभारी हैं मोजेस परमार। ओएम इंडिया का लक्ष्य दुनिया के उन हिस्सों में चर्च को मजबूत करना है, जहाँ वे अब तक नहीं पहुँचे हैं। ओएमसीसी दलित फ्रीडम नेटवर्क (डीएफएन) के साथ काम करती है। डीएफएन के सलाहकार मण्डल में विलियम आर्मस्ट्रांग शामिल हैं। विलियम आर्मस्ट्रांग, कोलोरेडो (अमेरिका) के पूर्व सीनेटर हैं और वर्तमान में कोलोरेडो क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी के प्रेसीडेण्ट हैं। यह यूनिवर्सिटी विश्व भर में ईसा के प्रचार हेतु मुख्य रणनीतिकारों में शुमार की जाती है। जोसेफ़ पिट्स ने ही नरेन्द्र मोदी को वीज़ा न देने के लिये कोंडोलीज़ा राइस से कहा था। जोसेफ़ पिट्स "कश्मीर फ़ोरम" के संस्थापक भी हैं। सुहासिनी हैदर, सुब्रह्मण्यम स्वामी की पुत्री हैं। सुहासिनी हैदर, सलमान हैदर की पुत्रवधू हैं। सलमान हैदर, भारत के पूर्व विदेश सचिव रह चुके हैं, चीन में राजदूत भी रह चुके हैं। रामोजी ग्रुप के मुखिया हैं रामोजी राव। रामोजी राव "ईनाडु" (सर्वाधिक खपत वाला तेलुगू अखबार) के संस्थापक हैं। रामोजी राव ईटीवी के भी मालिक हैं। रामोजी राव चन्द्रबाबू नायडू के परम मित्रों में से हैं। डेक्कन क्रॉनिकल के चेयरमैन हैं टी वेंकटरमन रेड्डी। रेड्डी साहब कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं। एम. जे. अकबर डेक्कन क्रॉनिकल और एशियन ऐज के सम्पादक हैं। एम. जे. अकबर कांग्रेस विधायक भी रह चुके हैं। एम. जे. अकबर की पत्नी हैं मल्लिका जोसेफ़। मल्लिका जोसेफ़, टाइम्स ऑफ़ इंडिया में कार्यरत हैं। वाय सेमुअल राजशेखर रेड्डी आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सेमुअल रेड्डी के पिता राजा रेड्डी ने पुलिवेन्दुला में एक डिग्री कालेज व एक पोलीटेक्नीक कालेज की स्थापना की। सेमुअल रेड्डी ने कहा है कि आंध्रा लोयोला कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उक्त दोनों कॉलेज लोयोला समूह को दान में दे दिये। सेमुअल रेड्डी की बेटी हैं शर्मिला। शर्मिला की शादी हुई है "अनिल कुमार" से। अनिल कुमार भी एक धर्म–परिवर्तित ईसाई हैं जिन्होंने "अनिल वर्ल्ड एवेंजेलिज़्म" नामक संस्था शुरु की और वे एक सक्रिय एवेंजेलिस्ट (कट्टर ईसाई धर्म प्रचारक) हैं। सेमुअल रेड्डी के पुत्र जगन रेड्डी युवा कांग्रेस नेता हैं। जगन रेड्डी "जगति पब्लिकेशन प्रा. लि." के चेयरमैन हैं। भूमना करुणाकरा रेड्डी, सेमुअल रेड्डी की करीबी हैं। करुणाकरा रेड्डी, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की चेयरमैन हैं। चन्द्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया था कि "लैंको समूह" को जगति पब्लिकेशन्स में निवेश करने हेतु दबाव डाला गया था। लैंको कम्पनी समूह, एल श्रीधर का है। एल श्रीधर, एल राजगोपाल के भाई हैं। एल राजगोपाल, पी उपेन्द्र के दामाद हैं। पी उपेन्द्र केन्द्र में कांग्रेस के मंत्री रह चुके हैं। सन टीवी चैनल समूह के मालिक हैं कलानिधि मारन। कलानिधि मारन एक तमिल दैनिक "दिनाकरन" के भी मालिक हैं। कलानिधि के भाई हैं दयानिधि मारन। दयानिधि मारन केन्द्र में संचार मंत्री थे। कलानिधि मारन के पिता थे मुरासोली मारन। मुरासोली मारन के चाचा हैं एम करुणानिधि (तमिलनाडु के मुख्यमंत्री)। करुणानिधि ने 'कैलाग्नार टीवी" का उदघाटन किया। कैलाग्नार टीवी के मालिक हैं एम के अझागिरी। एम के अझागिरी, करुणानिधि के पुत्र हैं। करुणानिधि के एक और पुत्र हैं एम के स्टालिन। स्टालिन का नामकरण रूस के नेता के नाम पर किया गया। कनिमोझि, करुणानिधि की पुत्री हैं, और केन्द्र में राज्यमंत्री थे। कनिमोझी, "द हिन्दू" अखबार में सह–सम्पादक भी हैं। कनिमोझी के दूसरे पति जी अरविन्दन सिंगापुर के एक जाने–माने व्यक्ति हैं। स्टार विजय एक तमिल चैनल है। विजय टीवी को स्टार टीवी ने खरीद लिया है। स्टार टीवी के मालिक हैं रूपर्ट मर्डोक। एक्ट नाउ फॉर हारमोनी एंड डेमोक्रेसी (अनहद) की संस्थापक और ट्रस्टी हैं शबनम हाशमी। शबनम हाशमी, गौहर रज़ा की पत्नी हैं। "अनहद" के एक और संस्थापक हैं के एम पणिक्कर। के एम पणिक्कर एक मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, जो कई साल तक आईसीएचआर में काबिज रहे। पणिक्कर को पदमभूषण भी मिला। हर्ष मन्दर भी "अनहद" के संस्थापक हैं। हर्ष मन्दर एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। हर्ष मन्दर, अजीत जोगी के खास मित्र हैं। अजीत जोगी, सोनिया गाँधी के खास हैं क्योंकि वे ईसाई हैं और इन्हीं की अगुआई में छत्तीसगढ़ में जोरशोर से धर्म–परिवर्तन करवाया गया और बाद में दिलीप सिंह जूदेव ने परिवर्तित आदिवासियों की हिन्दू धर्म में वापसी करवाई। कमला भसीन भी "अनहद" की संस्थापक सदस्य हैं। फ़िल्मकार सईद अख्तर मिर्ज़ा "अनहद" के ट्रस्टी हैं। मलयालम दैनिक "मातृभूमि" के मालिक हैं एम पी वीरेन्द्र कुमार। वीरेन्द्र कुमार जद (से) के सांसद हैं (केरल से)। केरल में देवेगौड़ा की पार्टी लेफ़्ट फ्रंट की साझीदार है। शशि थरूर पूर्व राजनैयिक हैं। चन्द्रन थरूर, शशि थरूर के पिता हैं, जो कोलकाता की आनन्द बाज़ार पत्रिका में संवाददाता थे। चन्द्रन थरूर ने 1959 में ''द स्टेट्समैन" की अध्यक्षता की। शशि थरूर के दो जुड़वाँ लड़के ईशान और कनिष्क हैं, ईशान हांगकांग में "टाइम्स" पत्रिका के लिये काम करते हैं। कनिष्क लन्दन में "ओपन डेमोक्रेसी" नामक संस्था के लिये काम करते हैं। शशि थरूर की बहन शोभा थरूर की बेटी रागिनी (अमेरिकी पत्रिका) "इंडिया करंट्स" की सम्पादक हैं। परमेश्वर थरूर, शशि थरूर के चाचा हैं और वे "रीडर्स डाइजेस्ट" के भारत संस्करण के संस्थापक सदस्य हैं। शोभना भरतिया हिन्दुस्तान टाइम्स समूह की अध्यक्षा हैं। शोभना भरतिया के के बिरला की पुत्री और जीड़ी बिरला की पोती हैं। शोभना राज्यसभा की सदस्या भी हैं जिन्हें सोनिया ने नामांकित किया था। शोभना को 2005 में पद्मश्री भी मिल चुकी है। शोभना भरतिया सिंधिया परिवार की भी नज़दीकी मित्र हैं। करण थापर भी हिन्दुस्तान टाइम्स में कालम लिखते हैं। पत्रकार एन राम की भतीजी की शादी दयानिधि मारन से हुई है।

# बुद्ध को मानों भी

अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ की ओर से देश में तमाम स्थानों पर गत् 25 मई को बुद्ध जयंती मनाया गया। कोशिश यह रही कि इस पर्व को मनाने में औपचारिकता ना रहे बल्कि भगवान बुद्ध के बताए दर्शन को व्यावहारिक रूप दिया जाए। बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर के प्रेरणा से ही दलित नवबौद्ध बने हैं और बन भी रहे हैं लेकिन साथ–साथ भारी मिलावट भी हो रही है। यह मिलावट मूलतः दो स्तर पर है। एक तरफ लोग अपने को डॉ. अंबेडकर के अनुयायी कहते हुए थकते नहीं तो दूसरी तरफ हिंदू धर्म के कर्मकांडों को भी मानने से परहेज नहीं करते हैं। विशेष तौर से नवबौद्ध दलित कर्मचारी–अधिकारी ही बने हैं और वे अपने गिरबान में झांककर के देखें कि क्या यह उन पर सही नहीं लागू होता। शादी–विवाह हो तो हिंदू रीति–रिवाज से और इस तरह से तमाम और बातें जैसे भाग्यवादी होना और जन्म लेने और मरने पर उन्हीं परंपरा को मानना, इत्यादि। दाल में नमक की मिलावट तो चल जाती है लेकिन यह मिलावट इतना अधिक ना हो कि दाल का मूल स्वरूप ही बदल जाए। वास्तव में डॉ. अंबेडकर के विचारों के साथ ऐसा ही हो रहा है। समयतंराल विचारों में शुद्धता आनी चाहिए लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। अंबेडकरवादी कम तो घोर जातिवादी ज्यादा। यदि बेटी का संबंध ना हो सके तो कम से कम रोटी का संबंध तो तेज होना चाहिए था, वह भी नहीं हो पा रहा है। डॉ. उदित राज ने ग्वालियर में बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य पर अपने विचार रखते हुए कहा कि केवल जुबान पर बुद्ध की बात करने से काम नहीं चलेगा बल्कि उसके लिए भगवान बुद्ध के त्रिशरण, पंचशील एवं चार आर्य सत्य जैसे दर्शन को व्यावहारिक जीवन में उतारना पड़ेगा। बैठकों और मंचों पर गला फाड़ कर भाषण देने से शायद ही कोई चूकता है लेकिन व्यावहारिक जिंदगी में शत्–प्रतिशत लोग कुछ और ही हैं। एक तरफ अंबेडकर और भगवान बुद्ध के अनुयायी कहलाने का श्रेय लेने से नहीं चूकते तो दूसरी तरफ जाति के आधार पर गुटबाजी या संगठन भी खड़ा करने में कोई संकोच नहीं होता। क्या इससे सामाजिक परिवर्तन हो सकेगा? भले समयतंराल, जागृति एवं शिक्षा के कारण कुछ सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक परिवर्तन हुआ हो लेकिन

यह गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि इससे विचारधारा का फैलाव हो रहा है। डॉ. उदित राज ने 4 नवंबर, 2001 को जब लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली तो नाम भी बदल लिया, क्या ऐसा साहस और कोई कर सका। यह असली संस्कृति एवं धार्मिक परिवर्तन है। दिखावे के लिए बौद्ध बने या हों, इससे विकल्प तैयार नहीं होगा और खिचड़ी से काम नहीं चलता। भले ही हम बेटी का संबंध ना कर सके तो कम से कम रोटी का संबंध तो स्थापित किया ही जा सकता है। हाल के समय में दलितों की विभिन्न जातियों में दूरी बढ़ी है और इसका मुख्य कारण राजनीति है। जाति के नाम पर राजनैतिक लाभ जल्दी लिया जा सकता है और इस लोभ–लालच के चक्कर में लोग जुबान पर सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों के नाम ओर व्यवहार में मनुवादी सोच रखते हैं। ऐसे में क्या नैतिक अधिकार बनता है कि हम सवर्णों से कहें कि वे जातिवादी भावना से ऊपर उठे। अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ का आह्वान है कि ना केवल सवर्ण विचारधारा के खिलाफ आंदोलन किया जाए बल्कि दलितों, पिछड़ों में से जो सामाजिक परिवर्तन का ढ़िढोरा पीटतें हैं उनका भी पोल खोला जाना चाहिए। परिसंघ यह मानता है कि पूरी तरह से शुद्धता तो नहीं आ सकती है लेकिन इतना भी खोखलेपन की बात नहीं होनी चाहिए कि नाम के लिए सामाजिक न्याय या परिवर्तन का आह्वान किया जाए लेकिन भीतर से मनुवादी बने रहें। ग्वालियर के बौद्ध सम्मेलन में डॉ. उदित राज ने कहा कि इस बौद्ध जयंती के ऊपर इतना तो संकल्प लें कि जो तथाकथित अछूत या शोषित हैं वे आपस में तो रोटी का संबंध की शुरुआत तो करें। हमारा समाज दोहरा चरित्र वाला है, उससे कोई बचा नहीं है और इसलिए यह मानकर चला जाए कि ये तथाकथित अछूत एवं शोषित भी उसी संस्कार से अभिशप्त हैं इसलिए उतना ही संकल्प लिया जाए कि जितना संभव हो। भाषण के मामले में ये भी पीछे नहीं हैं, यह कहने में जातिविहीन समाज की स्थापना करने में लगे हैं लेकिन जातिवाद करने में पीछे भी नहीं हैं।

# नक्सल समस्या का दूसरा पहलू भी है - डॉ. उदित राज

अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदित राज ने कहा कि नक्सल समस्या का समाधान केवल कानून व्यवस्था एवं आर्थिक विकास ही नहीं बल्कि सामाजिक भी है। माओवादी समस्या का हल निकालने के लिए दलित व आदिवासी नेतृत्व तैयार है यदि सरकार चाहे तो और वही प्रभावशाली होगा। 25 मई को जगदलपूर से 47 किलोमीटर दूर दरभा के झीरमघाट में छत्तीसगढ़ में जो नृशंस हत्या हुई, वह निश्चित तौर से बहुत ही अमानवीय व अलोकतांत्रिक है। सरकार से लेकर के जो अन्य लोग इस मामले में गंभीर हैं, हल निकालना चाहते हैं और भटके हुए लोगों को मुख्यधारा में शामिल कराना, उन्हें क्यों नहीं समझ में आता इसका सामाजिक पहलू भी है। बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं आंध्रप्रदेश के तमाम जनपद माओवादी और नक्सलवाद सक्रियता से प्रभावित है। कुछ स्थानों पर गरीबी एवं उत्पीड़न कारण हो सकते हैं तो कुछ जगहों पर जाति के आधार पर भेदभाव भी है। यह बात ना तो शासन–प्रशासन वालों को समझ में आती है और ना ही वार्तालापकारों को। इस घटना के बाद डॉ. उदित राज ने तमाम ऐसे वरिष्ठ लोगों से बात किया जो माओवाद और नक्सलवाद से परोक्ष या अपरोक्ष रूप से कभी जुड़े हुए थे। इस धारा के तमाम वरिष्ठ नेता जेलों में भी बंद हैं। श्री गदर, आंध्रप्रदेश के रहने वाले हैं और उनका इस आंदोलन से पूर्व में संबंध था और वे एक क्रांतिकारी गीतकार भी हैं, उनसे बात होने पर पता चला कि सरकार ऐसे लोगों को वार्तालापकार करने के लिए महत्व नहीं देती जो अनुसूचित जाति/जनजाति समाज से है। श्री कामेश्वर बैठा पलामू, झारखंड से सांसद हैं, वे भी व्यथित इस बात के लिए हैं कि सरकार उनका कभी प्रयोग नहीं किया। उनके क्षेत्र में माओवाद एवं नक्सलवाद ने पांव पसारे तो उसका मुख्य कारण सवर्णों द्वारा दलितों के ऊपर दमन। वे बताते हैं कि सरेआम दलित महिलाओं को नंगा कर दिया जाता था और बलात्कार करना तो सामान्य बात थी। दलित उत्पीड़न तो और स्थानों पर भी होता है लेकिन जिन स्थानों पर माकूल माहौल मिला जैसे जंगल आदि का शरण एवं माओवादियों एवं नक्सलवादियों का प्रभाव, वहां पर दलित आदिवासी धरना–प्रदर्शन एवं वोट की ताकत का इस्तेमाल ना करके हथियार उठाया। इनके अनुसार, 70 से 80 प्रतिशत तक माओवाद एवं नक्सलवाद के लड़ाकू दलित, आदिवासी समाज से ही है। कुछ लोग बड़े शहरों में रहने के कारण यह भूल जाते हैं कि इस देश के लोग जाति भावना से ऊपर नहीं उठे हैं और वह कहीं ना कहीं सोच का यह हिस्सा बना रहता है। सरकार की तरफ से सवर्ण बुद्धिजीवी एवं नेता वार्तालाप के लिए नियुक्त किए गए हैं लेकिन उनके परिणाम सामने हैं। हमारे यहां ज्यादातर लोग लोभ एवं लालची हैं इसलिए वे पहले अपने बारे में सोचते हैं फिर बाद में समाज व देश के लिए। अपना नाम चमकाने व फायदे के लिए गैर दलित व आदिवासी ही इस समस्या पर लेखक, पत्रकार एवं वार्तालापकार हैं। जिन लोगों को आगे करके समस्या का समाधान निकाला जा सकता है उनको शामिल तो करना तो बड़ी दूर की बात, बात करने के लिए भी तैयार नहीं हैं। कामेश्वर बैठा जी कई बार कह चुके हैं कि वे माओवादी नेताओं से सरकार की ओर से बात करने के लिए इच्छुक हैं लेकिन उनकी बात ही कोई नहीं सुनता। जब ऐसा अवसर आता भी है तो सवर्ण समाज के ही लोग आगे आते हैं।

डॉ. उदित राज ने आगे कहा कि वे स्वयं, गदर और कामेश्वर बैठा माओवादियों से बात करने के लिए तैयार हैं बशर्ते सरकार चाहे तो। इस घटना के बाद तमाम ऐसे लोगों से चर्चा हुई जो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से पूर्व में माओवादी आंदोलन से जुड़े रहे और जब उनसे कहा गया कि यदि सरकार सेना का प्रयोग करेगी तो माओवादी, नक्सलवादी का सफाया हो जाएगा। ये लोग क्यों नहीं सोचते तो जवाब में कहा गया कि यदि सफाया करने का अभियान चलता भी है तो माओवादी एवं नक्सलवादी छुप जाएंगे या दूसरे राज्यों में चले जाएंगे और अवसर मिलते ही फिर सक्रिय हो जाएंगे। इस तरह से सेना का प्रयोग समस्या का समाधान नहीं है। कानून–व्यवस्था, विकास, उत्पीड़न के अलावा यह एक बड़ा सामाजिक समस्या भी है। अगर इन बातों को ध्यान में रखकर के सरकार प्रयास करे तो काफी हद तक सफलता मिल सकती है। ठेकेदारों एवं अधिकारियों के खिलाफ तो रोष है ही साथ–साथ उन बड़े पूंजीपतियों के खिलाफ भी है जिन्होंने एक–दो दशक में खनन आदि से हजारों एवं लाखों करोड़ रूपए कमाए। इनका गुस्सा इस बात के लिए है कि सरकार बड़े पूंजीपतियों को जितना महत्व देती है उतना आम जनता का नहीं। छत्तीसगढ़ के एक–दो पूंजीपतियों के खिलाफ इनका रोष तो ज्यादा ही है जिन्होंने मुफ्त में कोयला लेकर के बिजली बनाया और बालको जैसे कंपनी को औने–पौने दाम में बेच दिया।

# सच बोलूं तो बुरा

डॉ. उदित राज

सवर्णों ने नहीं बल्कि अपनों ने मुझे बदनाम किया कि मैं बीजेपी और कांग्रेस का एजेंट हूं। यह मात्र अफवाह के रूप में वर्षों से नहीं रहा बल्कि गली–मोहल्ले तक तमाम लोगों ने इस इल्जाम पर विश्वास भी किया। अब मुझे लगता है कि जरूरी नहीं कि सच की जीत हो। एजेंट दो चीज के लिए बना जाता है पैसा या सत्ता। अतिरिक्त आयुक्त के पद को लात मारकर के समाज और देश के उत्थान में मैं आया हूं। यदि पैसा कमाना होता तो आयकर विभाग में ज्यादा अच्छा था ना कि कांग्रेस और बीजेपी के सामने हाथ फैलाऊं। सत्ता अगर इन्होंने दिया होता तो कोई ना कोई पद तो मिलता ही जो छुपता नहीं। इस तरह से मुझे तो कम कमजोर किया गया लेकिन समाज को कहीं ज्यादा। यदि मैं संसद में पहुंचा होता तो समाज को यह दिन ना देखना पड़ता कि वहां आवाज उठाने वाला कोई उपयुक्त आदमी नहीं है। पदोंन्नति में आरक्षण, खुदरा व्यापार में एफडीआई की इजाजत एवं दिल्ली विश्वविद्यालय में चार वर्षीय पाठ्यक्रम आदि जैसे ज्वलंत मुद्दे पर आवाज तो उठती। दिल्ली विश्वविद्यालय का चार वर्ष की बीए की ऑनर्स डिग्री दलित, आदिवासी एवं पिछड़ों को शिक्षा से बाहर रखने का षड्यंत्र है। संसद के बाहर रहकर के हम आंदोलन के जरिए 10 सांसदों से ज्यादा व्यवस्था को प्रभावित करते हैं तो अगर अंदर होते तो 131 अनुसूचित जाति/जनजाति सांसदों पर भारी पड़ता। गली–गली में शोर है कि मैं बहन मायावती जी को कमजोर कर रहा हूं तब क्या देश में एक ही दलित नेता होना चाहिए? क्या कोई कितने साल जिएगा, इसकी क्या गारण्टी है। कभी भी कोई मर सकता है तो क्या ऐसे में देश में एक ही दलित नेता रहे और अगर उसको कुछ हो गया तो क्या समाज नेतृत्वविहीन हो जाए। बाबा साहेब के निर्वाण के बाद कितने सालों तक समाज नेतृत्वविहीन रहा, क्या यह लोगों को पता नहीं है। मेरे खिलाफ तर्कहीन एवं तथ्यहीन दुःप्रचार किया जाता रहा है कि मैंने पार्टी बना दी। सवर्णों की आबादी हमारे मुकाबले में कितनी कम है, यह सब जानते हैं। फिर भी उनकी तमाम पार्टी एवं नेता हैं तो क्या दलितों में नहीं होना चाहिए? निजी क्षेत्र में पदोन्नति में आरक्षण जैसे मुद्दे के लिए बहन मायावती जी से मिलने को तैयार हूं लेकिन क्या बसपा में ऐसा कोई व्यक्ति है जो मिलवा सके या सुश्री मायावती से संपर्क करूं तो वे जवाब ही दे दें। ऐसे में मैं किस तरह से उनलोगों के बहन जी को कमजोर कर रहा हूं जो दिन–रात आरोप लगाते रहते हैं। किसी की हिम्मत हो तो इन बातों का जवाब दे या सुझाव दे। समाज हित में कुछ भी करने के लिए तैयार हूं।

# THERE IS ANOTHER ASPECT TO NAXAL PROBLEM – Dr. Udit Raj

Dr. Udit Raj, National Chairman, All India Confederation of SC/ST Organizations, said that the Naxal problem cannot be resolved only by addressing the law and order and economic problems of the disturbed area but also by addressing the social problems. Dalit and Adivasi leadership is ready to cooperate and tackle the Maoist problem if the Government so desired which will prove to be a lasting solution. On the 25th May, 2013, the brutal violence that took place at Darbha in Jhiramghat area of Chhatisgarh, is undoubtedly most inhuman and undemocratic. Both the Government and other agencies who are interested in finding a solution to this vexed problem to bring the Naxalites into the main stream, should understand that this problem has a social angle also. All the districts in Bengal, Bihar, Jharkhand, Odisha, Chhatisgarh, Maharashtra and Andhra Pradesh, are severely affected by Maoist and Naxalite activists. Some places are affected due to poverty while at other places, there is caste-based discrimination. It is high time that the administration and the negotiators take note of this stark reality and act accordingly. After this ghastly incident, Dr. Udit Raj had a serious dialogue with some of the senior and experienced people who were associated with Maoism and Naxalism directly or indirectly. Most of the senior leaders of these movements are lodged in jails. After holding talks with Shri Gadar, a resident of Andhra Pradesh and who was associated with this movement in the past and who is also a revolutionary balladier, I have come to the conclusion that the Government does not attach much importance for holding talks with people who are associated with the SC/ST community. Shri Kameshwar Baitha, who is also a Member of Parliament from Palamu, Jharkhand is also very unhappy with the fact that the Government has not made use of his influence in the area. The main reason for Maoism and Naxalism to have spread its wings in his area is the oppression of the upper caste people over Dalits. He often tells that Dalit women are openly made nudes in the area and molestation and rape are common in the area. Oppression and exploitation of Dalits and Adivasis take place in many parts of the country but wherever they found the help and shadow of Naxalism and Maoism and take up the guns and otherwise agitate and fight through democratic process. According to him, 70 to 80% of the Naxalites and Maoists belong to SC/ST category. Some urban people from Metro cities are just not able to understand the fact that the Indian society has still not been able to rise above the caste feelings which is an integral part of our social system. Very often Government nominates upper caste intellectuals for negotiations with Naxal and Maoist leaders but the results are there before the Government to see. In our country, most of the people are selfish and self-centred and they always think first about their own interests and then for the society or the country. With a view to come into limelight and take advantage of the situation, non-Dalit and non-Adivasi people have become writers, journalists and negotiators on this issue. The real people who should be brought on the forefront and who can help in resolving this vexed problem are not even consulted on this issue what to talk of associating them with the peace process. Kameshwar Baitha has expressed the opinion several times that he is willing to participate in the process of resolving this issue but nobody is prepared to listen to him. Even when such an opportunity comes, only people from the upper caste are associated with the process.

Dr. Udit Raj further said that he himself, Gadar and Kameshwar Baitha are ready to hold talks with Maoists if the Government so desired. After this ghastly incident, extensive discussions have been held directly or indirectly with people who were associated with Maoist agitation and told that if the Government deployed armed forces, Naxalites and Maoists can be wiped out from the affected area. The reply was that if the army is deployed to wipe out Naxalits and Maoists from the affected area, they will seek hideouts in forests or some other places. As such, use of armed forces is not a solution to this problem. Besides law and order and development, there is the problem of caste discrimination. If the Government tackles this problem in the light of issues raised above, we can achieve a considerable amount of success in this regard. There is not only people's anger against contractors and bureaucrats but also against capitalists who have been exploiting and earning lakhs and crores of rupees through illegal mining in the last two decades. Their main contention is that the Government does not give as much importance to the problems of the common man as they do it for capitalists. They are particularly very much against one or two big capitalists of Chhatisgarh who have a lot of money through illegal mining of coal which they used for making power plants and purchase BALCO at throw away price.

## Appeal to the Readers

You will be happy to know that the **Voice of Buddha** will now be published both in Hindi and English so that readers who cannot read in Hindi can make use of the English edition. I appeal to the readers to send their contribution through Bank draft in favour of **'Justice Publications'** at T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001. The contribution amount can also be transferred in 'Justice Publications' Punjab National Bank account no. 0636000102165381 branch Janpath, New Delhi, under intimation to us by email or telephone or by letter. Sometimes, it might happen that you don't receive the Voice of Buddha. In that case kindly write to us and also check up with the post office. As we are facing financial crisis to run it, you all are requested to send the contribution regularly.

**Contribution:**
**Five years : Rs. 600/-**
**One year : Rs. 150/-**

# Our Himalayan Neighbour Intrudes 20 KM Deep Into Our Territory

**R. L. Khanna**

The expansionist China has intruded 20 Km deep into our territory on the 15th April, 2013 at Daulat Beg Oldie sector in Eastern Ladakh valley along the unresolved 4057 km Line of Actual Control even when the peace process between the two countries has been at its high pitch.This is like the scenario which existed just before the 1962 war with China, the only difference being that at that time, China attacked India after the visit of the then Chinese Prime Minister Chou-en-lai to India amidst the camaraderie of 'Hindi Chini Bhai Bhai' and acceptance of the principles of Panchsheel but this time more than seven decades since the 1962 war, they have intruded 20 km deep into our territory before the impending goodwill visit of the Chinese Prime Minister and have openly refused to retrace their step. It is very likely that even when they are pressured or persuaded to go back, they will continue to stake their claims to areas which just do not belong to them. While China's policy towards India has become more aggressive and expansionist, our policy towards China continues to weak-kneed without any matching defense-prepared which gives the impression that we have not learnt anything even after burning our fingers as a result of the 1962 Indo-China war. China's expansionist plans with regard to territorial claims in the East with Japan and in the South with other neighbors from Vietnam to Philipines and massive defense-related infrastructure across our Line of Control should indeed have been an eye-opener for our policy makers but alas it is not so.They have built an extensive rail network and over 58000 km of roads in the area.It has got 30 divisions, each with 15000 soldiers near the Line of Actual Control which can outnumber the Indian forces by at least 3:1. Their airpower in the area is also tremendous with 15 fighter squadrons against us through the Tibet airfields along and it can be further augmented to 21 squadrons. In terms of conventional, nuclear and nuclear weapons and airpower, we are no match.The Indian political class and more so the defense and foreign policy makers have not learnt any lesson from the great humiliation suffered at the hands of the Chinese nor from their successive expansionist plans of defense prepared, infrastructure build-up, conventional and nuclear arms pile-up on our borders.

Our foreign policy with regard to our hostile neighbors has been week-kneed so far as our territorial integrity is concerned, right from the time of our first Prime Minister, Jawahar Lal Nehru. Just before the 1962 war, Pt. Nehru had commented with reference to that "not a blade of grass grows in that area" giving the impression that there is hard to surrender this land.The then Defense Minister Krishna Menon, in Nehru's Cabinet had also not much of a concern for defense preparedness. He had at one time commented that during peace time, the Indian armed forces could be utilized for civilian jobs including grass cutting forgetting that this cuts at the very roots of the concept of standing army and could prove disastrous for the morale of the armed forces.The horrendous consequences of Nehru's foreign policy regarding our territorial integrity and his Defense Minister Krishna Menon's utter lack of defense preparedness in the wake of provocative and aggressive designs of expansionist China resulted in the most humiliating defeat of the Indian army which is otherwise professional to the core and perhaps second to none in bravery and warfare. The Indian soldiers and officers who were captured as prisoners of war during the 1962 war were paraded on the streets of Beijing. The heads of some of the Indian soldiers were chopped off sent to the Indian side.

While addressing journalists described the 19-km Chinese intrusion at Daulat Beg Oldie sector in Eastern Ladakh on 15.4.2013, as a localized problem and would be resolved soon and further said that India does not want to accentuate the situation. Now the Indian and Chinese troops are standing face to face at a distance of just 100 metres.The Chinese have refused to retract from the intruded land. Thus, it is the Chinese who are accentuating the situation and their obduracy not to retract shows their evil designs and it is not a localized problem and needs to be tackled firmly and boldly. If we allow the situation to drift like this, China would like to lay their claims on the whole of India. Just because presently China is more powerful militarily and economically, we cannot allow them to brow-beat us and go on allowing them to usurp large chunks of our territory some through the machinations of Pakistan and sometimes on their own.

Where lies the fault? The fault squarely lies with our flawed policies. Even after more than five decades of the 1962 Indo-China war, there has been no drastic change in our foreign policy or the pattern of our defense preparedness. Typical of its lop-sided and lackadaisical approach, it was in early 2006 that the UPA I government finally gave the go-ahead for the creation of infrastructure in all the three sectors – Western (Ladakh), middle (Uttarkhand, Himachal) and Eastern (Sikkim and Arunachal), along the Line of Actual Control but here also the pace of development of the infrastructure work has been slow because of the bureaucratic red tape and green clearances and at the top of it political will. About seven years back in 2007, Defense Minister A.K. Antony paid a visit to a border post at Nathu La and after seeing the Chinese highway roads right up to their border posts, described the situation as an "eye-opener".

At least the Government should now wake up from its slumber and the Army Capability Development Plan of Rs. 26,155 crore along the Northern borders and the Eastern Infrastructure Development Plan of Rs. 9,243 crore should be implemented on a war footing much earlier than its targeted compltion date of 2020-2021 and 2016-2017 respectively if we have to meet the Chinese challenge and meet we must. Lack of funds should not be allowed to stand in the way of defense-oriented infrastructure development, latest arms and ammunitions, both conventional and nuclear and air bases. The defense sector equipment supplies should be opened to the private sector or FDI even beyond of 50%.

Given the above tools and a strong foreign policy, the Indian Army with the support of its 1125-crore people is quite capable of thwarting the nefarious designs of any aggressor. War is a very costly affair in the modern context but we should not forget the old saying that to maintain peace, we should be prepared for war. When we are prepared to defend ourselves, nobody can dare attack us. In some quarters, it is being argued that in terms of its economy, military might, both in conventional and nuclear weapons and air power, besides the advantage of infrastructure development and heights, China is way ahead of India and war in this context would be a great risk for India. In this regard, we should take a lesson from a small nation of diminutive people, Vietnam, who were pitched against the most powerful nation of the world, the United States of America. The tales of bravery, tenacity and nationalism of the people and army of Vietnam will always be proudly remembered in the annals of world history. Ultimately Vietnam could not be subjugated and the country rose again from the ashes and is now well on the way to progress in the comity of nations.

# LOWER PERCENTAGE OF NON RELIGIOUS SHOWS THE COWARDLINESS

**Kounteya Sinha**

LONDON: The latest Global Index of Religiosity and Atheism has found that the number of non religious people in India has risen but this is non-significant as compare to other countries. To be atheist needs courage and intelligence. A foolish person cannot be atheist. This survey also purports that Indian society is least flexible and hence it is quite conservative. Non other than caste is more responsible for this. The day non religious and atheists equivalent to China and Japan will grow in India, its progress will be of the level of these countries.

As against 87% saying they were religious in the same survey in 2005, the percentage has fallen to 81% in 2013. In other words, a drop by 6% in seven years.

Globally, the trend is similar. Religiosity has dropped by 9%, while atheism has risen by 3%. The report says there is a notable decline across the globe in self-description of being religious.

Pakistan is among the few countries which has seen an increase in the number of people who call themselves religious - by 6%.

Argentina, home to the present Pope, saw a 8% dip in people calling themselves religious.

South Africa has seen a 19% dip in those calling themselves religious, US 13%, Switzerland and France 21% and Vietnam 23%.

A total of 51,927 persons were interviewed globally from 57 countries across the globe in five continents. In each country a national probability sample of around 1000 men and women was interviewed. China has the highest number of atheists living in a single country with nearly 50% of its population describing themselves as non-believers compared to an average of 13% across the world.

**( Courtesy : The Times of India)**

**A MATTER OF FAITH**

**THE INDIAN STORY**

81% say they are religious

13% are not religious

3% are convinced atheists

**Where atheism is gaining ground (figures in percentage)**

| Country | Religious | Not religious | Convinced atheist | Don't know/ no response |
|---|---|---|---|---|
| China | 14 | 30 | 47 | 9 |
| Japan | 16 | 31 | 31 | 23 |
| Czech Republic | 20 | 48 | 30 | 2 |
| France | 37 | 34 | 29 | 1 |
| South Korea | 52 | 31 | 15 | 2 |
| Germany | 51 | 33 | 15 | 1 |
| Netherlands | 43 | 42 | 14 | 2 |
| Austria | 42 | 43 | 10 | 5 |
| Iceland | 57 | 31 | 10 | 2 |
| Australia | 37 | 48 | 10 | 5 |
| Ireland | 47 | 44 | 10 | 0 |

# VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 16 ● Issue 13 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● 16 to 31 May, 2013

## बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं।

-डॉ. उदित राज

# Joint Action Front For Democratic Education (SC/ST/OBC/LEFT) held a Demonstration at Sonia Gandhi's Residence to Protest Against DU 4- Year Degree Course

**Dr. Udit Raj, convenor of the Front and others participating in the demonstration at Sonia Gandhi's Residence.**

Joint Action Front For Democratic Education (SC/ST/OBC/LEFT) organized a demonstration on 19th May, 2013 at 10 Janpath, New Delhi (Smt. Sonia Gandhi's residence) and a large number of teachers, students and concerned people joined to ventilate their grievances. This action could have been avoided if our concerns were redressed by the authorities. The Vice Chancellor of Delhi University is not ready to budge an inch and meetings with Human Resource Development Minister and Secretary yielded no results. Of course , the Prime Minister showed the concern for the hurry to implement four year undergraduate programme but that again could not stop the move of VC. There are about 600 Universities in the country and it is only Delhi University which is bent upon introducing 4-year degree course based on the American pattern of education. If at all, education policy of the country needs to be changed, the initiative for the same should come from Government of India and not the Vice-Chancellor of a particular University. Policy formulation is not the job of a Vice-Chancellor. It is highly misleading and baseless on the part of the Delhi University Vice-Chancellor to say that it falls within the autonomy of University. In fact, the Vice-Chancellor has flagrantly encroached upon the domain of the Government to frame policies.

If the 4-year degree course is introduced in Delhi University, it will have an additional financial burden on the students. Students from Dalit, Adivasi and Backward categories , poor students from rural and urban areas and students passing out with regional languages as their medium of instruction, will be hit by this course to the maximum. It is very likely that some students may not seek admission to this course out of a sense of fear and even when they muster the courage to join such a course they may end up dropping it mid-session. This encourages the inequality in the same degree, i.e., Diploma, Bachelor and Honors which will create a sense of inferiority complex among the students. Teachers were not given an opportunity to go through the proposed syllabi before giving their suggestions and during the meeting, they were forced to give their suggestions on 11 Foundation Courses, 18 subjects of Discipline I , six subjects of Discipline 2 and four applied subjects which was next to impossible in such a short span of time. If these communities are stopped at lower level, they will be further marginalized and unlike USA, here higher education degree is more connected with dignity, income, status and participation. Members of Academic Council and the Executive Council of Delhi University were offered so many incentives and pressurized to pass the resolution on the 4-year degree course but the truth came to the surface when a large number of teachers from Delhi University passed a resolution against the 4-year course at their general body meeting on 12.5.2013. In the Foundation Course , 35 marks will be allocated for continuous projects , in Discipline I, 25 marks will be allocated for internal assessment , in Discipline II, 25 marks will be allocated for internal assessment and it is precisely this methodology also that will be used for discrimination against the SC/ST/OBC students. It is because of this pattern of evaluation that the SC/ST/OBC of Engineering and Medical students are made to fail in the examinations resulting in suicides and what not. The same situation will prevail for SC/ST/OBC students in the proposed 4-year degree course. It is also not clear as to how the Honors students of the 4-year degree course from Delhi University will seek admission in other Universities and vice versa.

Under normal circumstances, there would have been no need to hold a demonstration at your residence. We demand that a Committee of Eminent Persons is constituted for this purpose and after an in-depth study of the the matter, the four-year course may be introduced, if it is deemed fit. The best course would be to hold a discussion across the country on this issue and then the Ministry of Human Resource Development may formulate and introduce a policy on this matter, if it is considered necessary. Why is the Government not probing the fact as to why the Delhi University Chancellor is hell bent to introduce the four-year course in such a big haste? Is there any hidden agenda? Janata Dal (U) , Lok Janshakti Party, CPM and CPI have supported our view points and more political parties and organizations will back us in the days to come. It was demanded that this new curricula is stopped immediately and Vice Chancellor is dismissed.

**A large no. of teachers from different Universities in Delhi & office bearers of the Front taking part in the demonstration at Sonia Gandhi's Residence.**

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.
Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com Computer typesetting by N. K. Karn